

पत्नी को छोड़ गुजरात नहीं जाना पड़ेगा राजू को



जमीनी हालात-7

ऐसा माना जाता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (नरेगा) की सफलता के कारण भी ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस को लोकसभा चुनावों में काफी वोट मिले. इसीलिए हम पेश कर रहे हैं नरेगा का लेखा-जोखा. इस सीरीज में हम इस योजना की जमीनी हालत बताने की कोशिश कर रहे हैं. आप पढ़ चुके हैं झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और महाराष्ट्र का हाल. आज पढ़िए राजस्थान के बारे में.

संजय बोहरा जयपुर

जयपुर में मालवीय नगर निवासी सुरेश सिद्धा परेशान है कि उनके मकान पर काम करने वाले मजदूर आए दिन काम छोड़ जाते हैं। मजदूरी भी बेतहाशा बढ़ गई है। यह नरेगा की देन है। राजस्थान तो वैसे भी 2007-08 में अव्वल रहा है। न्यूनतम मजदूरी 60 रुपये से 100 रुपये है। गर्मियों में सुबह 7 से 11 बजे तक ही काम करवाते हैं।

भवन निर्माण ठेकेदार शंकरलाल सैनी कहते हैं कि तीन महीने नरेगा में बाकी उसके कारण खेतों में ज्यादा मजदूरी मिलने लगी है तो शहर क्यों आएंगे? दो वर्ष पूर्व डूंगरपुर में सर्वप्रथम नरेगा लागू होने के बाद इस संवाददाता को मजदूर राजू ने बताया कि नरेगा के कारण उसे पत्नी को छोड़ कर गुजरात नहीं जाना पड़ेगा। सूरत के हीरा उद्योग से

हिन्दुस्तान



वर्ष	अनुदान	खर्च	मानव दिवस	जॉब कार्ड
2006-07	83712	69306	998	15
2007-08	89676	86648	1082	28
2008-09	321199	350253	5231	81
2009-10	7081545	10098	6428	87

राज्य में नरेगा से संबंधित विवरण

राज्यों का प्रदर्शन	2006-07		2007-08	
	राजस्थान	भारत	राजस्थान	भारत
परिवारों ने काम मांगा	195862	63683	181094	97889
प्रति जिला लाख मानव दिवस	166	45	139.86	40.14
प्रति परिवार औसत कार्य दिवस	85	44	77	41
100 दिन का काम प्रतिशत	54	34	42	11
प्रति जिला खर्च करोड़ रु	116.60	44.06	125.97	44.01

आंकड़े ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार से। 2009-10 के आंकड़े 27 मई तक।

छंटनी होकर वापस घर आए प्रवासी मजदूरों के लिये नरेगा का ही सहारा है। मजदूर किसान शक्ति संगठन के निरखिल डे कहते हैं कि नरेगा से ग्रामीण क्षेत्र मंदी से अछूता रहा। लोगों की जेब में पैसा जा रहा है और वह अनाज, शिक्षा व अन्य जरूरतों पर खर्च कर रहे हैं। लेकिन समय पर मजदूरी नहीं मिलने की शिकायत बहुत बड़ी है। सेवा मंदिर के सर्वे में केवल 2 प्रतिशत लोगों ने 15 दिन में मजदूरी मिलने की बात कही। देरी होने के बदले एक भी व्यक्ति को श्रतिपूर्ति भत्ता नहीं मिला।

सरकार खुद मानती है कि 2007-08 में केवल 42 प्रतिशत लोगों को 100 दिन काम मिला, हर परिवार को औसतन केवल 77 दिन काम मिला और लगभग 75 प्रतिशत को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिली। तीन जिलों का सर्वे करके रिसोर्स इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन राइट्स के महासचिव विजय गोयल कहते हैं कि आवंटित पैसा निर्धारित समय में खर्च नहीं हो रहा और एक ही काम बार-बार दिखाते हैं।

पंचायती राज विभाग में सलाहकार गिरीश बूगरा कहते हैं कि मात्र 3-5 प्रतिशत भ्रष्टाचार है, वह भी निर्माण सामग्री में क्यों कि मजदूरी का पैसा चेक से सीधे खाते में जाता है।